States of America. For this purpose, the use of a relay transmitter located ir close proximity of U. S. A. will be necessary. This is to be attended to in the subsequent Five Year Plans.

However, a weekly composite magazine programme is prepared by the External Services Division for broadcast in U. K., Canada and Amrica and the tapes made available through the External Affairs Ministry for possible broadcast by some of the ethnic Radio Stations in U. S. A.

उत्तर प्रदेश और बिहार में दूरदर्शन का दूसरा चैनल

1499. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश और बिहार में दूसरा चैनल शुरू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी एन. गाडगिल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) दूरदर्शन की सातवीं योजना के लिए उपलब्ध संसाधनों के अन्दर दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास के चार महानगरीय शहरों को छोड़कर देश के किसी भी अन्य स्थान पर द्वितीय चैनल सेवा उपलब्ध करना सम्भव नहीं है ।

मंडल आयोग के प्रतिवेदन का लागू किया जाना

1500. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 अप्रैल, 1986 के दैनिक "पंजाब केसरी" में छपे इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि हैदराबाद में नवम आंध्र प्रदेश मुन्नुसकप महासभा सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए जल-भूतल परिवहन विभाग में केन्द्रीय राज्य मंत्री ने यह घोषणा की है कि मंडल आयोग की सिफारिशें जल्द लागू कर दी जाएंगी; और

(ख) आयोग की सिफारिशों के कब तक लागू कर दिए जाने की संभावना है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो): (क) सरकार का ध्यान प्रश्न में उल्लिखित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है । केन्द्रीय जल-भूतल परिवहन राज्य मंत्री ने निम्नलिखित वक्तव्य दिया है "मंडल आयोग की सिफारिशों" पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

(ख) जहां तक मंडल आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन का संबंध है, यह निश्चय किया गया है कि आयोग द्वारा तैयार की गई अन्य पिछड़े वर्गों की सूची पर जनमत प्राप्त किया जाए । इस तरह की जनमत प्राप्त करने की रूपरेखाएं (माडलिटीज) विचाराधीन थी बाद में, आरक्षण-विरोधी और आरक्षण-समर्थक आन्दोलनों के फलस्वरूप, देश के कुछ भागों में उभरती स्थिति को ध्यान में रखते हुए, गृह मंत्री ने मुख्य मंत्रियों को अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण पर राष्ट्रीय मतैक्य प्रकट होने तक पूर्व-स्थिति बरकरार रखने के प्रस्ताव पर विचार करने की बारे में पत्र लिखे थे और अधिसंख्य मुख्य-मंत्री इस सुझाव से सहमत हो गये थे । सभी राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों से आरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत तथ्यपरक सूचना मांगी गई थी तथा प्राप्त सूचना को राष्ट्रीय मतैक्य के प्रश्न पर चर्चा के दौरान उपयोग के लिए संकलित कर लिया गया है । मंडल आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों पर निर्णय की कोई नियत तिथि इंगित करना संभव नहीं है ।